Promotional avenues of Inspectors (Harijan Welfare) in the Directorate of Social Welfare, Delhi Administration

39. SHRI BHAGATRAM MANHAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1276 given in the Rajya Sabha on the 28th March, 1985 regarding posts of Inspectors in the Directorate of Welfare for SC|ST, Delhi Administration and state:

(a) whether it is a fact that Inspectors (Harijan Welfare) in the Directorate of Social Welfare, Delhi Administration have not been provided suitable promotional avenues so far;

(b) whether it is also a fact that they were denied the promotion to the posts of Deputy Superintendent as the Recruitment Rules in this regard were amended; and

(c) if so, by what time the present incumbents will be given long awaited promotions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) to (c) According to the recruitment rules applicable upto 10-12-1984, the Inspectors (Harijan Welfare) were entitled to be promoted to the next higher post of Deputy Superintendent|Superintendent. These rules were revised with effect from 11-12-1984. In terms of the revised recruitment rules, the Inspectors (Harijan Welfare) ceased to be eligible for promotion to the post of Deputy Superintendent. However, the new recruitment rules proposed to be implemented provide for re-introduction of the benefit of promotions to this category.

Smuggling of heroin on Indo-Pak Border

40. SHRI BEKAL UTSAHI:
SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that of late smuggling of heroin through the Indo-Pak border has increased; and

(b) if so, what are the details in this regard and what steps are being taken by Government to check such activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) and (b) Reports received indicate that the Indo-Pak border continues to be vulnerable to smuggling of heroin besides charas and other contraband goods. The quantities of heroin seized in India in the last three years where the source|origin of the drug was reported to be Pakistan are given below:

Year	Quantity (rounded off in kgs.)
1985	544
1986	2296
*1987	2292

*(Provisional)

Government have initiated various aggressive counter-measures against drug-trafficking which include strengthening of the preventive and intelligence machinery, adoption of a liberalised reward scheme for officers and informers, increased cooperation between various drug-law enforcement agencies, bilateral cooperation with Pakistan, and Regional Copperation under the umbrella of SAARC.

बन्द पड़े कपड़ा एकक

41. श्री मीर्जा इशाक़बेग : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा उद्योग में कितनी कपड़ा एकक बन्द पड़े हैं तथा इनमें से कितने एन०टी०सी० के अधीन हैं तथा ये कब से बन्द पड़े हैं, इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य में कितने-कितने मजदूर बेकार हो गए हैं तथा कब से इनमें से कितने एककों को फिर से चालू किया गया जो पुन: बन्द हो गए तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ख) कितने एककों को चालू किया जा सकता है तथा इस सम्बन्ध में क्या उपाय

किये गये हैं और इन्हें कब तक फिर से चालू किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) मजदूरों के संबंध में भावी योजनायें क्या हैं ; और

(घ) समग्र कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में क्या योजना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिये)।

(ख) नोडीय अभिकरण द्वारा विचार किये गये 107 मामलों में से 51 मिलें संभाव्य रूप से अर्थक्षम पाई गई। पुनर्वासन पैकेज तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन करने के लिये वित्तीय संस्थानों द्वारा इन मामलों को उठाया गया है। कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती कि उन्हें कब पुनः खोलने की सम्भावना है।

(ग) वस्त्र नीति सम्बन्धी जून, 1985 के विवरण में यह कहा गया है कि रुग्ण एककों को पुनः चालू करने की प्रक्रिया में तथा उन्हें बंद अथवा परिसमापन किये जाने की दशा में श्रमिकों के हित की पूरी तरह रक्षा की जायेगी। उन मिलों के कामगारों को जिन्हें 6 जून, 1985 को अथवा उसके बाद स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये एक वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि की स्थापना की गई है।

(घ) 1 अगस्त, 1986 से चल रही वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना में उन मिलों को आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है जिनका मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया प्रौद्योगिकी तथा उत्पाद मिश्रण आदि को उन्नत करना है।

विवरण

राज्य	एन टी सी	अन्य	योग	रजिस्टर दर्ज कुल कामगार	रू०
आंध्र प्रदेश	—	3	3		1389
बिहार	—	1	1		500
गुजरात	1	32	33		53158
हरियाणा	—	2	2		5292
कर्नाटक	—	10	10		8312
केरल	—	2	2		1328
मध्य प्रदेश	—	3	3		5813
महाराष्ट्र	—	13	13		25091
राजस्थान	—	7	7		8264
तमिलनाडु	1	36	37		17662
उत्तर प्रदेश	3	9	12		21400
पश्चिम बंगाल	1	9	10		28016
योग	6	127	133		176225

इन बंद मिलों में से 1 मिल 1967 में, एक 1970 में, दो 1976 में, दो 1981 में, आठ 1982 में, चौदह 1983 में, 16 मिल 1984 में, 7 मिल 1985 में, 33 मिल 1986 में तथा 49 मिलें 1987 में बंद की गयीं। कामगारों को उस दिन से बेरोजगार माना जाता है जिस दिन से मिल विशेष को बंद किया जाता है।

उन एककों की संख्या देना सम्भव नहीं हैं जिन्हें पुनः चालू किया गया और बाद में पुनः बंद कर दिया गया, क्योंकि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी वस्त्र मिल को कुछ समय के दौरान कुछ सहायता दिये जाने के बाद, वह स्वतः कार्य क्षम हो जायेगी। किसी विशेष समय पर वस्त्र मिलों को जीवन क्षमता अथवा अन्य बातें विभिन्न कारणों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये कारण किस समय क्रियाशील हो जायेंगे इसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

Loan melas organised by the Nationalised Banks

42. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nationalised banks have been organising melas for the distribution of loans to the needy; and

(b) if so, what is the number of such public functions for the distribution of loans to the needy organised by the nationalised banks since 1981 till 31st December, 1987, alongwith the dates, the amount disbursed on each occasion and the names of the banks which participated in these loan melas and also the places where these functions were held?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Banks organise credit camps as part of their overall measures to accelerate the flow of credit to weaker sections and also to bring about greater awareness amongst them of assistance available from banks. It is not possible to indicate the number of such camps held since no central monitoring of credit camps is considered to be either feasible or necessary. However, as at the end of September 1987, Public Sector Banks had outstanding advances of Rs. 6506.06 crores involving 2.05 crores borrowal accounts in favour of weaker sections of society.

राष्ट्रीयकृत बैंकों का आवास कार्यक्रम

43. श्री मीर्जा इर्शादबेग : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवास निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कितना प्रतिशत योगदान है तथा इस सम्बन्ध में उनका भावी कार्यक्रम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरियो) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1986 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आवास निर्माण के लिये वित्त प्रदान करने के वास्ते 183.09 करोड़ रुपए की रकम दी थी, जो वर्ष के अन्त में बकाया अग्रिमों का 0.34 प्रतिशत बैठती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी बताया है कि समग्र आवास वित्त नीति पर फिर से विचार किया जा रहा है और जैसे ही नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, वैसे ही भावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी।

Central assistance for the construction of canals in Rajasthan

44. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the amount of Central assistance given for the construction of canals in Rajasthan during the last three years; and

(b) the number of canals constructed in Rajasthan during this period and the acreage of land being irrigated thereby?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a)